



घर पहुंचने की ज़हजहट... फिर बारिश फिर जाम

भोपाल। राजधानी में बारिश में हर बार उभरने वाला दृश्य कल फिर नजर आया और लोग देर रात तक घर पहुंचने की ज़हजहट करते रहे। वह यह कि मुख्य सड़कों ऐसा जाम लगा था अच्युत सड़क की जाम हो गई। दरअसल दोपहर से तेज बारिश के बाद शाम को दरतरों के छूने से का वर्क हुआ तो एम्पी नगर जौन-1 से लेकर जीजी पलाईओवर और राती कमलपति रेलवे स्टेशन के सामने तक करीब 40 मिनट से ज्यादा समय तक घटे भर तक ट्रैफिक जाम की रिश्ति रही। पलाईओवर पर एबुलेस भी फंसी दिखी।

राजधानी के साथ-साथ ऑफिस टाइम में लौट रहे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हवीबांज नाके तक वाहन रेंगत नजर आए। जीजी पलाईओवर के अंत में, यानी हवीबांज नाके के पास बारिश का पानी भर जाने से गड़ियां धीमी हुईं और ट्रैफिक जाम लग गया। बारिश की बजह से सड़क पर फिसलन और जलभराव ने हालात को और बिगाड़ दिया। यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई।

आरोप-लीज पर दे रहा भेल खेल-दशहरा मैदान पर भेल की नजर पड़ने से भड़के लोग पहुंचे मंत्री के पास



भोपाल दोपहर मेट्रो

राजधानी के भेल क्षेत्र में बरखेड़ा लफ खेल एवं दशहरा मैदान के अधिग्रहण के विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं। इनमें कई लोग स्थानीय विधायक व मंत्री कृष्णा गौर के बंगले पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भेल ने बाउड्रीवॉल बनाकर मैदान को लीज पर दे दिया। मंत्री गौर ने इस मामले में भेल प्रबंधन से चर्चा करने की बात कही है।

जानकारी के मुताबिक भेल युवा संगम समिति के बैठकरत्ते लोगों मंत्री के बंगले पर पहुंचे थे। पूर्व पार्श्व कंकल मिशन ने बताया कि पिछले 10 साल से मैदान पर सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी जा रहे हैं। वहीं, क्रिकेट, कबड्डी, बालीबॉल टूर्नामेंट भी होते हैं। पहले मैदान डब्लू-खाबड़ था, जिसे लोगों ने मिलकर 300-400

ट्रक मिट्टी डालकर समतल किया। इसी मैदान का अधिग्रहण भेल प्रबंधन ने किया है, जो ठीक नहीं है। नाराज लोगों ने कहा कि भेल ने इस मैदान को बाउड्रीवॉल बनाकर लीज पर दे दिया है। जिसका विरोध रहवासी लगातार कर रहे हैं। मंत्री से मिलकर उन्हें अपनी समस्याएं बताई गईं। मंत्री गौर ने रहवासियों को आश्वासन दिया कि वे भेल प्रशासन से बात करेंगे। वहीं रहवासियों का कहना है कि अगर उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो वो उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे।

उत्तर कल मंत्री बंगले पर घेराव की जानकारी मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई। बंगले के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। ताकि, कोई किसी प्रकार का हाहाकारा को फैसला है कि भवियत में पार्क में किसी भी निजी या

जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अब शहर की प्रेम नगर बस्ती में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिससे क्षेत्र के 70 से अधिक निवासियों की जांच की गई। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य जांच और परामर्श देना था। शिविर के दौरान, लाभार्थियों का रक्तचाप और शुगर स्टर की जांच की गई।

इस दौरान जांच में चौंकाने वाला था सामने आया कि कुल 15 रोगियों में उच्च रक्तचाप और शुगर की समस्या पाई गई। हैरानी की बात यह रही कि जहां शिविर में 5 साल के बच्चों से लेकर 74 साल के बुजुंगों तक का चेकअप किया गया, वहीं



भोपाल दोपहर मेट्रो

ये 15 मरीज जिनकी आयु 35 से 50 वर्ष के बीच थी, इन्हीं में यह समस्या अधिक देखने को मिली। यह अंकड़ा इस आयु वर्ग में जीवनशैली से जुड़ी लीभारियों के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है। इस मोक्ष पर जुड़ा अध्यक्ष डॉ. कुलदीप गुप्ता ने बताया कि शिविर में उच्च रक्तचाप और

से बचाव के लिए दवाइयां भी पिलाइ गईं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक कदम है। इस स्वास्थ्य शिविर को सफल बनाने में डॉ. पल्लवी, डॉ. प्रियल पांडे, डॉ. रमेश और डॉ. गुरुशरण सिंह सहित कई अन्य चिकित्सकों ने अपना योगदान दिया।

शुगर को नियन्त्रित करने के लिए खनन-पान प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। डॉक्टरों ने मरीजों को उचित आहार और जीवनशैली में बदलाव के बारे में विस्तार से समझाया। इसके अतिरिक्त, महिलाओं में खक्की की कमी (एनीमिया) को दूर करने के लिए सुतुलित आहार के संबंध में महत्वपूर्ण परामर्श दिया गया।

बच्चों को कृपि (पेट की डेंगे) से बचाव के लिए दवाइयां भी पिलाइ गईं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक कदम है। इस स्वास्थ्य शिविर को सफल बनाने में डॉ. पल्लवी, डॉ. प्रियल पांडे, डॉ. रमेश और डॉ. गुरुशरण सिंह सहित कई अन्य चिकित्सकों ने अपना योगदान दिया।

'एक पेड़ मां के नाम'



'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत गुलमोहर कॉलोनी में पार्श्व सुषमा बांधीसा, कर्मचारी नेता व समाज सेवी अजय श्रीवास्तव नील, पूर्व पार्श्व फैरवे, राहुल यति आदि ने शहीद अजय यादव पार्क में वक्षायाण कार्य किया।

मैट्रो एंकर

गौतम की सफलता परिषद के सहयोग और मार्गदर्शन का परिणाम

नव युवक परिषद के छात्र गौतम सेना में अधिकारी बने

हिरदाराम नगर, दोपहर मेट्रो

नव युवक परिषद के हेनहार छात्र गौतम भांधानी के भारतीय सेना में एक कमीशंड अधिकारी बने हैं। उनकी सफलता परिषद के मार्गदर्शन एवं सहयोग का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो भवित्व के नेतृत्वकर्ताओं को गढ़ने में परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

गौतम भांधानी की यह यात्रा, परिषद के एक प्रयोगित छात्र से भारतीय सेना में एक प्रतिष्ठित अधिकारी बनने तक, उनके स्वयं

के अटूट समर्पण और परिषद के

उस गहन संकल्प की जीवन्त प्रमाण है जिसके तहत प्रतिभावान किंतु विचारित युवाओं को सशक्त बनाया जाता है। उनकी यह नियुक्ति केवल

नव युवक परिषद: एक दशक पुराना सेवा भाव

जिसकी स्थापना परमहंस संत हिरदाराम साहिब जी के पावन आशीर्वाद से हुई थी। यह संस्था वर्षाना में पूर्य सिद्ध भाक जी के सम्मान और प्रेरणाप्रद मार्गदर्शन में स्वालित हो रही है। परिषद विचारित युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहायता प्रदान करने, प्रतिभावान युवाओं के करियर विकास को समर्पण देने और उन्हें आस्पनिर बनाने के लिए समर्पित है।

साल 1978 में स्थापना

वर्ष 1978 में अपनी स्थापना के बाद से, परिषद ने विश्वभर के उदादाताओं के अमृत्यु सहयोग से 12,000 से अधिक छात्रों को शिक्षित कर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। परिषद द्वारा छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में रक्त फैसला भी भुगतान, यूनिफॉर्म, पार्ट्युप्टुक्क, कॉर्पोरेशन स्टैशनरी और सभी विद्यायी की नि-शुक्र कोशिंग शामिल हैं। इस पुरीत मिशन में 300 से अधिक समर्पित स्वयंसेवक नियर्वाय भाव से जुड़े हुए हैं, जो परिषद के उद्देश्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

3A

जकल सहरी परिवहन के लिये नये साधन के रूप में एप आधारित टैक्सी सेवा बड़ी जरूरत बन गई है। शहरों-महानगरों में सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं की वजह से अम आदीवी आवश्यकता पड़ने पर ऐप आधारित कंपनियों के बाहरों से अपने गंतव्य तक आवाजाही कर लेता है लेकिन अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नए दिशा-निर्देश लागू होने के बाद ऐसे वाहनों से सफर महंगा होने की स्थिति में अब लोगों को कई बार सोचना पड़ेगा। अबल तो व्यस्त समय को कारण बनाकर समान दूरी तक सफर के लिए दोगुना किराया लेना अनुचित है, फिर यह बहद निराशजनक है कि पहले ही महंगाई के बोझ से बेच आम लोगों पर किराए की मार के साथ-साथ बुकिंग रद्द कर देने पर जुमाना लगाने का

राहरी परिवहन के मामले में बढ़ेगी दिक्कतें

नियम भी सख्त कर दिया गया है। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। इससे यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा पाया गया है कि कैब कंपनियों की गाड़ियां समय पर नहीं आती। ऐसे में लोगों को विवश होकर अपनी बुकिंग रद्द करनी पड़ती है। वहीं चालकों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है। के बार यात्रा का डिजिटल भूमान करने पर जोर देते हैं और पसद का गंतव्य न मिलने पर खुद भी बुकिंग रद्द कर देते हैं। हालांकि अब ऐसे चालकों की नकल करने के लिए उन पर जुमाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन चिंता की बात यह

है कि राज्य सरकारों को नए दिशा-निर्देश लागू करने की सलाह के बाद आम लोगों पर ही इसका आर्थिक बोझ बढ़ेगा। व्यस्त समय में किराया बढ़ाने का चलन नया नहीं है। मार मूल्य निर्धारण का यह मनमाना तरीका आखिरकार यात्रियों की जेब पर भारी पड़ता है। कैब सेवा प्रदाता कंपनियों को दोगुना किराया लेने की अनुमति देने से पहले यात्रियों की शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने की जरूरत थी। हाल में एक सर्वेक्षण में आधे से अधिक यात्रियों का कहना है कि इन कंपनियों की सेवाएं बेहतर नहीं हैं। कई बार तो गाड़ियों के लिए

देर तक इंतजार करना पड़ता है। वाहनों की साफ-सफाई और चालकों के खारब व्यवहार पर भी लोग प्राय-स्वाल उठाते रहे हैं। अचानक किराया बढ़ा दिए जाने से लोग पहले ही प्रेरणा थी। अब तो सांधे-सीधे लोगों की जेब से दोगुना किराया वसूलने की व्यवस्था थोप दी गई है। नए दिशा-निर्देश से आखिरकार आम लोगों को ही नुकसान होता है। यह सच है कि तमाम दावों के बाद भी लोगों की आय में वैसा इजाफा नहीं हो रहा है जिस तरह से जरूरतें और महंगाई बढ़ रही है। इसलिये बेहतर तो यह होता कि सरकार इस सेवा से खबर लेती। अब लोग यदि एप आधारित इस सेवा से खबरें तो उनके पास सार्वजनिक परिवहन का मजबूत विकल्प भी नहीं है। ऐसे में कई बार मजबूरी में लोगों को अनुचाहे ही इस मूल्यवृद्धि को भी झेलना पड़ेगा।

आज का इतिहास

8 जुलाई 1972 को सोरभ गांगुली का जन्म कोलकाता में हुआ था। वे भारत के महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने साल 1992 में भारतीय टीम के लिए वनडे डेब्यू और साल 1996 में टेस्ट डेब्यू किया था। इसके बाद बार्बाद तक इस स्तर बल्लेबाज ने अपने करियर के दौरान कई शानदार पारियां खेली और ढेर से रन बनाए। उन्होंने कुल 113 टेस्ट मैचों और 311 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 16 शतक और 35 अर्धशतकों के साथ 7212 रन बनाए तथा उनके 22 शतक और 72 अर्धशतकों के साथ 11363 रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कसानी के रूप में भी भारतीय टीम को कई जीत दिलाई है। गांगुली ने 49 टेस्ट मैचों में कसानी करते हुए 21 जीत वासिल की, जिसमें भारत के बाहर 11 जीत शामिल थीं। वनडे में उन्होंने 146 मैचों में भारतीय टीम की कसानी की, जिसमें 76 में जीत मिली। गांगुली इंडियन प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं। वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है।

- 1497 - पुराणी नाविक बाक्सों दा गामा ने यूरोप से भारत की प्रथम जलयात्रा आरंभ की। वे समुद्र से भारत की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय बने थे।
- 1792 - फ्रांस ने पर्शिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी।
- 1833 - रूस और तुर्की ने रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किये।
- 1836 - आज ही के दिन महान वैज्ञानिक तार्मस डार्विन शोध करने सेंट हेलेना पर पहुंचे थे।
- 1889 - अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल का प्रकाशन शुरू हुआ।
- 1912 - भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनीतिज्ञ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास का जन्म।
- 1914 - कम्युनिस्ट राजनीति के प्रतापह, वामपक्षी नेता एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय तक कार्यरत रहे ज्योति बुजु का जन्म आज ही के दिन हुआ था।
- 2020 - भारतीय सिनेमा के मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप का निधन आज ही के दिन हुआ था।
- 2021 - हिंमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन।
- 1937 - तुर्की, ईरान, इराक और अफगानिस्तान ने सौदाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए।
- 1937 - हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, सशक्त कथाकार, नाटककार और आलोचक परिचय किशोर का जन्म।
- 1939 - भारतीय राजनीतिज्ञ गंगा प्रसाद का जन्म।

एसवाई कुरैरी

Jब भारत के चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से ऐन कछ महीने पहले मतदाता सूचियों में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) किए जाने की घोषणा कर दी, तो इससे राजनीतिक हल्कों के कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई। हालांकि चुनाव आयोग इस कवायद का बातावर संवेदनाविक अनिवार्यता बताकर कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 326 में यह जस्ती है कि केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही मतदाता के हक्कदार हैं। आयोग के मूलाभिक, वर्तमान संशोधन का उद्देश्य सूचियों में सुधार करके यह प्रावधान याकीनी बनाना है। इस विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के तहत 2003 की मतदाता सूचियों में जिनका नाम शामिल था, उन्हें संत्वापित मतदाता माना जाएगा। अतीत में भी चुनाव आयोग उन जगहों पर गहन संशोधन करने के आदेश देता आया है, जहां उसे मतदाता सूची की विश्वासीयता संदर्भ या पुरानी लंगों हालांकि, जिन लोगों का नाम 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल हुआ है या जिन्होंने नाम कभी शामिल नहीं कराया- उन्हें अब नागरिकता की च्यू-घोषणा और अन्य सहायक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाणपत्र या माता-पिता का प्रमाणपत्र जमा कराना होगा। इसके पीछे घोषित इदाहा चुनावी डेटाबेस अपडेट व शुद्ध करना है। लेकिन, ईमानदार दिखने वाली अनेक अन्य प्रक्रियाओं की तरह यहां भी छिपी चतुराई विवरण में स्पष्ट हो जाती है।

मतदाता सूचियों को संशोधित करने का विचार नहीं है। वास्तव में, 2003 की कवायद के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने कई पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में बड़े पैमाने पर गहन संशोधन प्रक्रिया की चाली थी। हालांकि, तब इन संशोधनों को चुनावी से ऐन पहले नहीं कराया गया था, न ही चुनिदा मतदाता सूची के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता थी। इससे पहले भी, बिहार सहित 20 अन्य राज्यों में चरणबद्ध तरीके से इसी क्रिया की चाली थी। एसआईआर मतदाता पंजीकरण का आधारभूत अवयव है- विशेषतया बड़े पैमाने पर हुई कवायदों में जैसे परिसीमन, किसी क्षेत्र में उत्तर-पूर्वत उपरांत शांतिकाल या डिजिटलकरण। 2003 व 2004 के बाद से वार्षिक सारांश संशोधन सामान्य प्रक्रिया बन गये। साल 2004 के बाद किसी भी राज्य को चुनाव आयोग के संचेतन निर्णय चालित गहन संशोधन नहीं करना पड़ा, व्याप्तिकृत घर-घर सर्वेक्षण के बाद आवाजाही करने वाली राजनीतिक स्पीकर्स थी। स्पार्टित प्रथा से विचलन व जिस वक्त यह कवायद की जा रही है, वह बिहार में इसे विवादास्पद बनाता है।

निस्सदैह, मतदाता सूचियों को नियमित अपडेट किया जाना चाहिए- लेकिन बिहार जैसे बाह-ग्रास्ट, उच्च-प्रवासन वाले राज्यों में मतदाता सूचिकल चार महीने पहले ऐसा करना इसे बहुत पुरिकल काम बनाता है। चिंता वैधान की नहीं, बल्कि व्यावहारिकता व कायाक्रम से उपजने वाली राजनीतिक दृश्यवाली को लेकर है। मूलतः, यह संशोधन प्रमाण पेश करने का भार मतदाता पर डाल रहा है। जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें अब दस्तावेजी साक्षणों के साथ अपनी प्रमाणिकता साबित करनी होती है। सैद्धांतिक रूप में भले यह उचित लगता हो, किंतु व्यावहारिक पटल पर इससे उन लोगों को मताधिकार करने से बचना की खात्र बन जाता है, जिनकी कायाक्रम पर जारी हो जाती है। जबकि चुनाव आयोग का दावा है कि एसआईआर चुनावी प्रक्रिया है-न कि नागरिकता की पड़ावाल इस मूले को और जटिल बनाता है, व्यापक परामर्श का अभाव। विपक्षी दलों का आरोप है कि विशेष गहन संशोधन को बिना किसी पूर्व सूचना का या उनसे चर्चा किए बिना शुरू कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने 2002-03 में 20 राज्यों में एसआईआर और पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में 2004 के संशोधन करने के दौरान, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के साथ पहले मूल्यांकित करना चाहिए।

ऐसे वक्त में, संस्थान यह वास्तव देकर कि वह तो विवरणीयता खो सकते हैं। वाकियों की तरह, बिहार के मतदाता भी इसके बाहर छूट जाने की एक बात नहीं होती। लेकिन लोकतंत्र में कानूनी अवयव एकमात्र पैमाने नहीं होता बल्कि नीतिक वैधता व जनता का भरोसा उठने ही मायने रखता है। चुनाव आयोग को नेतृत्व करने के लिए नियमित अपनी विवरणीयता खो देने

